पर्यावरण रक्षा से जुड़ा विकास का मॉडल 'ग्रीन डील'

भारत डोगरा

विकास के बारे में एक भ्रामक सोच काफी समय से फैलाई गई है कि पर्यावरण की रक्षा करने पर अधिक ध्यान देना विकास की राह में एक बाधा है। इस सोच को फैलाने वाले लोग वास्तव में तो यह कह रहे थे कि पर्यावरण की रक्षा की नीतियां ऐसी कंपनियों के तेज़ प्रसार में बाधा बन सकती हैं जो जल, जंगल, ज़मीन का विनाश कर या बहुत प्रदूषण फैला कर तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। भ्रम यह फैलाया गया कि पर्यावरण रक्षा की नीतियां समूचे विकास की राह में ही बाधक हैं।

जलवायु बदलाव के दौर में इस अनुचित सोच का परिणाम यह रहा कि सारे देश ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने को एक बोझ मानने लगे और कहने लगे कि इससे उनके विकास में कठिनाई आएगी। इसमें सच्चाई इतनी ही है कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयले और तेल पर आधारित गतिविधियों में कमी लानी पड़ेगी क्योंकि इनसे ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन होता है। पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अक्षय ऊर्जा का पूरा मार्ग खुला है और इसमें तेज़ी से आगे बढ़कर जो विकास होगा वह पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा होगा, हालांकि कुछ सावधानियां तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में भी उठानी पड़ेंगी।

यदि सार्थक विकास को ठीक से परिभाषित किया जाए और सस्टेनेबल विकास की बात की जाए तो यह पर्यावरण की रक्षा पर ही आधारित हो सकता है। मिट्टी, हवा, पानी, वनों को बचाया जाएगा तभी तो भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा और वे भलीभांति अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगी।

जलवायु बदलाव जैसे गंभीर पर्यावरण संकट को देखते हुए कई पर्यावरणविदों व संगठनों ने पर्यावरण की रक्षा पर आधारित विकास के मॉडल के विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं जिसे ग्रीन मॉडल कहा गया। इस मॉडल में अधिकतम निवेश अक्षय ऊर्जा पर, ऊर्जाकुशल आवास पर, वनीकरण पर, वनों की रक्षा पर, जैविक खेती के प्रसार पर, अधिक श्रम-सघन व छोटी परियोजनाओं पर किया जाएगा। हथियारों के प्रसार पर रोक लगेगी। इसके साथ यह जोड़ना ज़रूरी है कि यह अर्थव्यवस्था सादगी व समता पर आधारित होगी।

लगभग पांच वर्ष पहले विश्व के अनेक महत्त्वपूर्ण व धनी देश तेज़ी से आर्थिक व वित्तीय संकट की ओर बढ़े तो पर्यावरण संगठनों ने ग्रीन मॉडल की इस मांग को नया रूप दिया ताकि इससे आर्थिक संकट से बाहर निकलने की राह भी नज़र आए। ऐसे प्रस्तावों को 'न्यू ग्रीन डील' जैसे नाम दिए गए। इससे पहले 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में जो बड़ी आर्थिक मंदी अमरीका में आई थी उससे बाहर निकलने के लिए वर्ष 1933 में राष्ट्रपति रुज़वेल्ट ने 'द ग्रेट डील' की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत जन-हितकारी कार्यों और आर्थिक ढांचे को मज़बूत करने में श्रम-सघन तरीकों पर बड़ा निवेश किया गया। इससे आर्थिक संकट से बाहर निकलने में व बेरोज़गारी दूर करने में मदद मिली।

'न्यू ग्रीन डील' के समर्थकों का मत है कि यदि मौजूदा आर्थिक संकट के दौर में अक्षय ऊर्जा स्रोतों, बिजली की बचत, पर्यावरण अनुकूल खेती, उद्योग व भवन-निर्माण में पर्यावरण रक्षा के अनुकूल बदलावों में भारी निवेश किया जाए तो इससे एक ओर जलवायु बदलाव का संकट कम होगा, ऊर्जा संकट भी हल होगा तथा साथ ही आर्थिक संकट व बेरोज़गारी दूर करने में मदद मिलेगी। इस तरह पर्यावरण की रक्षा को विकास की मुख्यधारा में लाने का यह प्रयास सराहनीय है और इसे बहुत रचनात्मक बनाया जा सकता है। अपने देश में हमें यहां की ज़रूरतों के अनुसार ग्रीन डील का एक बेहद रचनात्मक और सार्थक प्रारूप तैयार करना चाहिए। ***(स्रोत फीचर्स)***